27,103 करोड़ से इन्फ्रा व इंडस्ट्री को लगेंगे पंख

पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने इस मद में रखे थे 23,990 करोड़ रुपये, इस बार नौ प्रतिशत की वृद्धि

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के बजट में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है, जो कि चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है। वहीं, राज्य में सतत औद्योगिक विकास के लिए अटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 2,000 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। इस राशि से राज्य में नए औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक पार्क व जोन विकसित किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के लिए 23990.76 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने के लिए सरकार औद्योगिक निवेश पर जोर दे रही है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार का अवस्थापना और औद्योगिक संरचनाओं के विकास पर जोर है। मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण व नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। औद्योगिक विकास विभाग के अनुसार यह राशि नए औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तारीकरण पर खर्च की जाएगी। योजना के तहत सभी जिलों में 50 से 100 एकड़ में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य सरकार पिछले वर्ष से ही भूमि अधिग्रहण करा रही है। विभाग की कोशिश है कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी व अन्य बुनियादी सुविधाओं को विश्वस्तरीय बनाया जाए। इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की होगी।

राज्य में विदेशी निवेश को बढ़ावा: सरकार ने राज्य में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि का प्रविधान किया है। यह राशि फार्च्यून-500 कंपनियों द्वारा राज्य में किए जाने वाले निवेश को लेकर उन्हें प्रोत्साहन के रूप में जारी की जाएगी। पिछले वित्तीय वर्ष में लखनऊ में अशोक लेलैंड ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण के लिए भारी निवेश किया है। इसके अलावा जापान व यूएई की कई कंपनियां राज्य में बड़ा निवेश कर रही हैं।

युवाओं को निशुल्क टैबलेट के लिए 2,374 करोड़ रुपये: स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत सरकार ने युवाओं को निशुल्क टैबलेट वितरित करने के लिए बजट में 2,374 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। हालांकि, अभी तक यह राशि खर्च नहीं की जा सकी है। इसके बाद भी सरकार ने युवाओं के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 374 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए हैं।

230 एकड़ भूमि ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी के लिए पीपीपी के तहत प्रस्तावित। इसके अतिरिक्त 1,510 एकड़ भूमि का आवंटन भी हो गया है पूरा

13 राज्य अधिनियमों की 99 प्रतिशत आपराधिक धाराओं को अपराध मुक्त किया गया है। साथ ही निवेश मित्र 3.0 की शुरुआत भी की गई है

12 प्लेज पार्कों की व्यवस्था की गई है बजट में। योजना का उद्देश्य निजी भागीदारी से 10 से 50 एकड़ भूमि पर आधुनिक औद्योगिक पार्क का विकास करना है, भूमि आवंटन शुरू

5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण और नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के लिए की गई

1,000 करोड़ रुपये के फंड आफ फंड्स की व्यवस्था उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए की गई है

1000 करोड़ के बजट का एफडीआइ और फार्च्यून-500 कंपनियों के निवेश के लिए किया गया है प्रस्तावित

2374 करोड़ रुपये की व्यवस्था स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना में टैबलेट व स्मार्ट फोन वितरण के लिए